New Sankalp India | Ease of doing Business

हिंदुस्तान के एक सौ तीस करोड़ नागरिक तय करें की मेरे लिए ये संकल्प होगा कि मैं ये करूंगा.

नमस्कार, new India संकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज हम ease of doing business यानी कारोबार करने में आसानी या कारोबार सुगमता के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे. व्यापार के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो व्यापार करिए और व्यापार भी अगर कोई करना चाहे तो कई लोगों का यह भी कहना होता है कि व्यापार तो हमारे ज़माने में होता था तब बड़ा आसान था. कुछ लोग यह कहते हैं कि व्यापार करना शुरू करना तो आसान है उसको चलाए रखना बड़ा मुश्किल है और कुछ लोगों का यह कहना है कि हमने यह क्यों कर लिया? लेकिन दूसरी तरफ उसके उलट यह भी कहा जाता है कि जो जितना बड़ा जोखिम लेता है उसको लाभ भी उतना ज़्यादा होता है. व्यापार अपनी ओर आकर्षित करता है. व्यापार से समाज जुड़ते हैं व्यापार से देश और देश जुड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं. पिछले कुछ वर्षों में ease of doing business को लेकर भारत ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई हैं और इस तरह अगर हम देखें तो भारत का यह report card बहुत ही शानदार है. किस तरह का है? पहले film दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे पहले film.

Make in India के रास्ते पर आगे बढ़ रहे भारत ने देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं. पहले किसी को अपना कारोबार शुरू करना होता था या फिर किसी विदेशी company को यहां निवेश करना होता था तो वो यह सोचकर ही पीछे हे जाती थी कि भारत में प्रक्रिया बहुत जटिल हैं, जिसमें बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में बहुत सार्थक परिवर्तन हुआ है. अनेक स्तर पर उलझे system को आज सरकार business और citizen friendly बनाने की दिशा में काम कर रही है. पिछले चार साल में देश में एक हज़ार चार सौ से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया जा चुका है. पहले देश में commercial dispute को सुलझाने में करीब करीब चार साल लग जाते थे. तमाम प्रयासों के बाद इसे अब कम करके चार सौ दीनो पर ले आया गया है. Imported सामान की clearance में दो हज़ार चौदह से पहले औसतन जहां दो सौ अस्सी घंटों का समय लगता था वहीं आप यह समय घटकर एक सौ चौवालीस घंटे का भी नहीं रह गया है. पर्यावरण मंजुरी जिसे मिलने में पहले वर्षों और महीने लग जाते थे. अब वैसी या कुछ हफ्तों में ही मिल जाती है. GST ने देश के logistic sector को भी मत किया है. पहले के मुकाबले अब turnaround time में करीब करीब पंद्रह प्रतिशत की कमी । है. इससे समय भी बच रहा है और कंपनियों का पैसा भी. श्रम कानूनों का पालन करने के लिए पहले उद्यम को पचास साठ अलग अलग register भरने पड़ते थे. सरकार अब इन register को कम करके पांच पर ले । है. छोटे छोटे दुकानदार छोटी छोटी उद्यम देर तक अपनी दुकानें खुली रख सके इसके लिए भी कानून को बदला गया है. GST से जुड़े छोटे कारोबारियों को अब एक करोड़ का loan सिर्फ उंसथ minute में मिल जा रहा है. इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने market का दायरा बढ़ाने, license और जांच से जुड़ी उसकी परेशानी कम करने के लिए भी कई फ़ैसले लिए गए हैं. एक ऐसा work culture विकसित करने पर जोर दीया जा रहा है जिसमें form जमा करने दस्तावेज़ दिखाने या fee जमा करने के लिए सरकारी दफ्तर या किसी और agency के office में जाने की ज़रूरत ही ना हो. इस तरह का work culture policy driven governance को और सशक्त करेगा. सरकार ने इस दिशा SPICe+ के रूप में नई पहल है. इसके तहत corporate मामलों के मंत्रालय श्रम मंत्रालय राजस्व के भाग और वित्त मंत्रालय से जुड़े clearance सिर्फ एक भी पहुंच SPICe+ के माध्यम से ही संभव हो पाएगा. SPICe+ की शुरुआत तेईस फरवरी से की गई है. Ease of doing business के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए से भारत में कारोबार करना अब और आसान हो गया है. World bank की ease of doing business में चौदह ranking की सुधार के साथ भारत तिरसठ में स्थान तक पहुंच गया है. उम्मीद है कि इन प्रयासों से भारत करोबारीयो ke लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

व्यापारिक गतिविधियों से हम सबकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है. भारत तिरेसठ number पर है इस index में जिसे ease of doing business कहते हैं इसका क्या अर्थ है? और किस तरह से यह पूरा परिदृश्य बदला है विस्तार से समझ के लिए खास मेहमान हमारे साथ यहां studio में मौजूद हैं. हम उनका परिचय कराते हैं हमारे साथ हैं श्री K.V.R Murthy आप joint secretary हैं ministry of corporate affairs बारह सरकार की बहुत स्वागत आपका साहब. हमारे साथ है आशीष गर्ग आप present हैं institute of company secretary of India. बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद. हमारे साथ है श्री मनोज पांडे आप joint हैं ministry of corporate affairs और साथ ही आप CEO हैं IEPF के बहुत स्वागत है आपका और हमारे अगले मेहमान श्री अपने गुप्ता जी आप present हैं institute of chartered accountants of India और साथ ही यहां studio में हमारे साथ chartered accountants हैं जाने माने जो अर्थशास्त्र को समझने वाले लोग हैं वह यहां पर इस चर्चा में हमारे साथ यहां शामिल रहेंगे और अब हम बात शुरू करते हैं और सबसे पहले Murthy साहब मैं आपसे शुरू करता हूं. अगर हम व्यापार शुरू करने की बात करते हैं. अब मैं और अब से कुछ साल पहले में क्या तब्दील। है? देखिए भारत सरकार का यह संकल्प रहा है कि ease of doing business अपने देशवासी को मिले और ना सिर्फ ही मिले लेकिन यह महसूस भी हो यह भारत सरकार का संकल्प रहा है. तो तकरीबन चार साढ़े चार साल पहले हम लोगों ने जायज़ा लेना शुरू किया था इस बात का. तो हमने पाया कि एक आम आदमी अगर एक company शुरू करना चाहता है तो उसे company का नाम reserve कराने के लिए और company का गठन कराने के लिए कितना time लगता है, इसका जायज़ा लेना शुरू किया. तो हमने पाया कि तकरीबन चौबीस stars of companies के दफ्तर हैं हमारे देश भर में और इन चौबीस registered के में name reservation यानी नाम को reserve कराने के लिए आपकी company का और फिर company का गठन कराने के लिए. पंद्रह से बीस दिन average यानी औसतन time लगता था. हमने यह भी देखा कि यह जो चौबीस कार्यालय थे, इसमें uniform नहीं थी. कई जगह पर ज़्यादा time लगता था. कई जगह पर कम time लगता था और लोगों की सोच के मुताबिक application process होते थे. हमने यह भी देखा कि कई cases में एक आम आदमी को छह महीने तक लग गए, नाम का reservation कराने के लिए. Inincorporation कराने के लिए साल भर का time भी लग जाता था कुछ cases में. तो हमने फिर तय किया कि इसकी तो reengineering करनी पड़ेगी process की. तो पिछले चार साल में कई कदम उठाए गए जिसके तहत एक central registration center बनाया गया. उसके बाद कई सारे incorporate integrated information form बनाए गए. तो आज हम यह कह सकते हैं confidence के साथ कि name reservation और company का गठन औसतन तीन से चार घंटे के अंदर आपको जवाब ज़रूर मिलेगा. अगर आपकी application दुरुस्त है आपको approval मिलेगी और अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा कि उनकी हम किस तरह से दूर किया जा सकता है? जी. मनोज पांडे जी यही बात थोड़ा सा और विस्तार से हम समझना चाहेंगे जो Murthy साहब कह रहे हैं कि पहले एक एक साल का वक्त भी लग जाता था नाम कराने में या company शुरू करने में. अब यह जो सुविधा जो है जितनी जल्दी जो यह काम हो हो रहा है या अब होने लगा है, क्या यह सिर्फ कुछ बड़े शहरों में दिल्ली और मुंबई में ही हो रहा है या पूरे भारत में यह व्यवस्था है. नही जैसा मूर्ति साहब ने कहा अभी यह central है पूरे भारतवर्ष के लिए एक central center है यह. जहां यह processing हो रही है. इसको थोड़ा सा विस्तार की कोशिश जैसे company का नाम होने वाली. एक व्यक्ति एक company का नाम या दो इनमें से कोई एक नाम चाहते हैं आप approve करिए. तो मूर्ति साहब जो कह रहे थे कि इसमें छह छह महीने और इतना वक्त लगता था कि नहीं था. चौबीस जगह और वहां verify होगा मान लीजिए यहां नहीं तो किसी और जगह वही नाम registered है. तो नहीं मिलेगा. जी. जी तो अब अभी जैसे वह उसमें कुछ rules को standard हमने किया कि यह rules कुछ होनी चाहिए जिनको follow करना है. So name rules sorry incorporation rules companies की है. फिर जो central center है

उसमें वह बिल्कुल ही paper less है वहां Automated system है. कहीं बैठे आप देश की किसी कोने से जी. आप कम तीन incorporate करा सकते हैं और नाम ले सकते हैं. नाम reserve करा सकते हैं. यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है. आप घर बैठे अपने दफ्तर में बैठे apply कर सकते हैं. अगर आपके pass papers हो, so आप computer के माध्यम से apply कर सकते हैं और आपको name reserve आपकी company का हो जाएगा और companies भी incorporate हो जाएंगी. चूंकि कुछ rules से कुछ कानून है उनको आपको follow करना है. अगर सब कुछ दुरुस्त है. So तकरीबन आज के आज के दिन में तो हमारा centralized center है. वह एक तरीके से प्रति दिन जी करीब करीब अट्ठानबे प्रतिशत application process कर देता है. अगर मान लीजिए वह application के मूर्ति आपने कहा कि working hours में अगर नौ दस बजे के बीच में आ गए. जी. So आधे दिन में आपकी application process हो गई और तकरीबन पांच सौ छह सौ कंपनियां incorporate हो रही है. इन्हीं एक दिन के अंदर so आपने आप में एक मिसाल है यह. Because आप अगर देखें तो हमारा देश बड़ा है और प्रति माह. करीब करीब दस हज़ार company incorporate होती है. प्रतिदिन प्रति माह प्रति माह, प्रदीप महा जी. और एक साल मैं आप समझे कि औसतन एक आद company हो गई अगर ऐसे करें औसतन तो. उनका निपटा उन एक centralized center से हो रहा है जहां officers हैं और हमारे साथ में supporting के staff है. जिस तेजी से यह काम हो रहा है यह एक मिसाल है अपने आप में क्योंकि तीन चार घंटे में आपको name reserve हो जाता है आपका. काफी company का company incorporate हो जाती है. बैठे आपको कहीं जाना नहीं है. आप दफ्तर में बैठे घर apply कर दिया. जैसे आप बता रहे हैं सुबह apply कर गया और तीन चार घंटे में यह approval हो गया नाम अगर आपके सारे papers ठीक हैं, अगर आपने वह document पेश as per rules कर दिया. जी. तो आपको तीन चार घंटे में आपका आपकी बन गई. पांच सौ छह सौ company आपकी प्रतिदिन बन रही है रोज़ाना रोज़ाना. आपको बिना आकर लग गया हज़ार आपने बताया एक महीने में. जी हां और भी ना कहीं गए हुए. आपको physical movement कहीं नहीं करना है. Physical records नहीं file कुछ online. यह सब online है और all online हीं आपको form process होकर भी आ रही हैं. आपको certificate of inincorporation मिल रहा है. जी, उसी के साथ और PAN TAN दो सुविधा cool generate हो रही है. So आपको PANnumber मिल जाता है उस पर time number मिल जाता है और आपको certificate of ininincorporation मिल जाता है. यह एक अपने आप में हमारे बहुत से दर्शकों को जो जो इस विषय को बहुत नहीं जानते PAN तो सभी लोग समझते लेकिन TAN क्या होता TAN जहां detect जहां होता है detect को number लेना वह tax के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है हमारे income tax department से हमारे बीच में जो समझौता है. उसकी वजह से एक company apply करती है company को certificate of ininincorporation मिलता है उसे PAN number मिल जाती. कम को अब company अपनी काम को शुरू कर सकती है. शुरुआत हो सकता है. ठीक. उसी के तहत जैसे processing reengineering होना शुरू हुआ. So और thought process बढ़ी. सरकार की सरकार ने कहा इसे और और कैसे सुविधा दी जा सकती है और सुविधाओं को कैसे प्रदान किया जा सकता है. जो अभी जो पांडे जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने दो बार यह बात कही अगर आपके कागज़ पूरे हों ठीक. तो अगर आपके कागज़ पूरे हो तो अक्सर मैं आपके अनुभव से समझना चाहता हूं जो लोग company के लिए apply करते हैं. सुभाष जिन्होंने apply किया. अब अमूमन किस तरह के कागज़ हैं जिनमें कमी रह जाती है या लोग अक्सर गलतियां करते हैं जो जिनको नहीं करनी चाहिए क्या क्या रहता है उनका अनुभव जरा आप इस side से बताए जरा. पिछले बीस वर्षों में पूरे systems को अच्छे से बात हैं. और एक समय होता था कि जब पहले number apply करने के लिए आपको Roc के office में जाना पड़ता था भी लंबी ला लगती थी. चालान जमा कराने के लिए वह पांच सौ रुपए की fees होती थी उसके लिए अलग अलग लगती थी. जी. उसके बाद में memorandum छप छुपा है memorandum सात

submit करना है common seeds बनवा है. जी. तो practically आपको एक company को बनाने के लिए कम से कम तीन से चार बार पहले आपको Roc के office में जाना है और उसके बाद वह सुविधा जो ऐसे आपने कहा कि दूध दराज इलाके में तो उन लोगों को सिर्फ चौबीस office में ही आना है. तो वह अगर मान लीजिए example है कि वह ऐसे इलाके में है जहां पर वह office है ही नहीं तो उसको शायद दो सौ चार सौ kilometer दूर उसको travel भी करना है. लेकिन अब जो है इस नए जो हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से देखा और हम इसको काफी appreciate करते हैं कि इसमें दोनों चीज़ों में change आया. इसमें कानून में भी change आया. जैसे बहुत सारी चीज़ें खत्म कर दी गई कि आपको common feel नहीं चाहिए. आपको referendum का printing नहीं चाहिए. और उसी तरीके से जो जो technology का use किया गया जो आज जैसे सबने ने बोला कि SPICe+ जो अभी हम बात करेंगे लेकिन एक minute के लिए हम कर सकते हैं जिसमें बात लगी उससे पहले भी अगर मैं बात करूं पिछले तीन चार वर्षों में कि आपका online चालान हो गया आपका memorandum हो गया. तो यह सारी facilities आने से even जो दूर राज के इलाके के लोग हैं अगर उनके pass internet सुविधा ठीक से है तो वह वही बैठे बैठे. अपने घर पर बैठे बैठे company registered करा सकते हैं हम आज चर्चा कर रहे हैं जिसको हम ease of doing की बात कर सकते हैं. जी for the company formation. अब बात आती है कागज़ की कौन से कागज़ चाहिए? Expose कीजिए आपने नाम रखा तो नाम जो होता है वह post की कीजिए नाम आपका किसी से coins से example की बात किया भारत नाम रखना चाहते तो आपको नाम allowed नहीं होगा क्योंकि उसकी कुछ restrictions होती हैं, guidelines होती हैं कि आप कौन सा नाम ले सकते हैं और कौन सा नाम नहीं ले सकते? Same way में fail नाम आपको किसी दूसरी company का already available है तो वह आप नहीं ले सकते. आपके director के जो आपको identification देने हैं वह proper पूरे हैं या नहीं है. अगर एक व्यक्ति जब apply करता है और उसको इस बात का समझ है कि मुझे कौन कौन से कागज़ लगाने हैं तो वह अपने आप में सु की बात जब हम कर रहे हैं तो वह सु से काम जो है वो complete हो जाता है और जो मैं यह कहूंगा कि 90 percent cases के अंदर आज की तारीख में achieve होता है जो लोगों को इन सब चीज़ों की आज अच्छी समझ है. जी बिलकुल. एक छोटी सी बात जो आपकी बात से निकल आ रही है पांडे जी जो बात जो कागज़ की जो बात हो रही है तो online में यह भी फ़ायदा है कि आपने सुबह apply किया और कहीं कोई कमी है तो आपको उसी दिन पता चल जाएगी. जैसे कि पहले system था कि आपने apply किया उसमें कोई कमी है तो फिर जैसे हफ्ते आपके बार बार गए दस दिन बाद गए आप आइएगा तो आपको यह कागज़ पूरी नहीं है यह पता होने में भी काफी वक्त गुज़र जाता था. कागज़ात मतलब उसे जैसे यह मोह है यह वह है यह सब electronic है. अगर आपने इन लोगों को ठीक attach किया है, ठीक से भरा है. तो जैसा मैंने कहा कि करीब करीब नब्बे से पचानवे प्रति application same day process हो रही हैं. जी. आपको online पता लग जाएगा कि यह कमी है. अगर आप चाहे तो आप उसी दिन उसको फिर से वापस बन सकते हैं और वापस जैसे ही आप भरे आपको कम corporate हो जाएगी. बिलकुल ठीक है. आशीष जी मैं आपसे यहां यह अब यह जानना चाहूँगा जो बात चर्चा में आ रही है देखिए देश बहुत बड़ा है और कहीं कहीं फिर वह बात भी आती है कि दूर दराज का इलाका है, कोई व्यक्ति वहां internet की सुविधा सुविधा है नहीं है. क्या इसमें ऐसा भी है कि जिस व्यक्ति को access नहीं है computer की या इस तरह से या अब किसी भी व्यक्ति को जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है अपना कारोबार शुरू करना चाहता है. अब उसके लिए ज़रूरत है कि आप जैसे किसी भी विशेषज्ञ के chartered accountant के pass ही जाना पड़ेगा क्योंकि कुत्तों से समझ में आएगा नहीं क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए company से secret और chartered accountants, company inincorporation में सबसे भूमिका में करने निभाते हैं. पर उसके बाद इतना easy e form है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी बड़ा लिखा है, समझदार है अब चूंकि यदि व्यक्ति company बना रहा है तो उसका एक vision है. वह

entrepreneur बनना चाहता है, company बनाना चाहता है तो उस form को खुद भी भर सकता है. सारे fake की उस पर available हैं. अच्छा जहां तक बात है company से cr की chartered accountants की तो वह हमेशा से available है. हर शहर में available है. आप देखेंगे लगभग साठ हज़ार company से cr आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा हैं. तो हर company से creative और chartered accountant किए थी हम पूरी संख्या को मिलाएं. तो हम लोग ministry के आम के रूप में ही काम करते हैं और हम चूंकि ministry के अंतर्गत आते हैं. हम statue body है under under the act of parliament. तो हमें पूरा सहयोग ministry से मिलता है जब भी नया form आता है उसका discussion होता है उसके ऊपर के ऐसे accuse हो सकते हैं, क्या problem आ सकती है उन सब सबको discuss करते हैं. तो उन forms को इतना easy बनाया गया है कि बिना Caa और से की सुविधा लिए भी साधारण व्यक्ति अपना कर सकता है. यह चाहिए भी बिल्कुल कर सकता है. अच्छा उसमें कोई उसको असुविधा सुविधाएं उसमें कोई असुविधा नहीं आती पर यदि वह अपनी सहायता ले लेते हैं तो शायद उनका काम ज़्यादा easy हो जाएगी. जो अक्सर ने बोला कि तीन से चार घंटे में company बन जाती है. तो यदि आपने सुविधा ली हुई है paper आपने पूरे दोस्त लगाए हुए है आपको पूरी process मालूम है तो काम जल्दी हो जाएगा. Otherwise हो सकता है एक आध बार उनके में कुछ problem आए थी सब submission में form आए, कोई त्रुटि निकाला जिन त्रुटि को वापस submit कर सकते हैं. सुनकर हैरानी होती है इतनी तेजी से भी चीज़ें होती है. जब अब आपसे भी आए अब यह समझना चाहेंगे और पांच में चर्चा में यहां लाना चाहूँगा. जब हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो SPICe+ form की जो बात है तो यह क्या है SPICe+. SPICe+ हमारी हमने पहल करी थी आज से तकरीबन पांच में चर्चा में यहां लाना चाहूँगा. जब हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो SPICe+ form की जो बात है तो यह क्या है SPICe+. SPICe+ हमारी हमने पहल करी थी आज से तकरीबन साढ़े चार साल पहले हमने एक integrated inincorporation form launch किया था उसका नाम था Inc 29. जिसमें तीन service मिलती थी जब आप नाम reserve कर सकते थे, number ले सकते थे और information ले सकते थे. फिर दो हज़ार सोलह में october दो दो हज़ार सोलह गांधी जयंती वाले दिन हम लोगों ने ने यह spice नाम के एक form का launch किया. उसका नाम था sp. Simplified performer for incorporate a company electronic. उसके तहत हम लोगों ने यह किया कि memorandum of association और articles association जो लगाई जानी चाहिए. Information application के साथ. पहले paper के रूप में उनको scan करके upload किया जाता था. इसको हमने digital रूप में है convert करा जिसके तहत एक st memorandum और एक standard articles of association उपलब्ध है किसी भी नागरिक के लिए attach करने के लिए. उसमें अगर वह कुछ बदलाव करना चाहता है तो बदलाव करने की क्षमता उस form में electronic form में है. तो यह इससे हमको यह सहूलियत मिलती है कि हम digital माध्यम से यह जान लेते हैं कि इसमें नागरिक ने क्या बदलाव किया और हमारी नज़र सीधा वह बदलाव के ऊपर जा आती है क्योंकि जो st performer है उसको तो बार बार check करने की ज़रूरत नहीं है. हमें speed लाना है हमें predict लानी है अपने processing में. लानी है. तो जो उसने बदलाव किए हैं हम लोग उसको देख लेंगे और जल्दी से जल्द हम लोग काम कर सकते हैं. फिर इसको हम लोगों ने और next level पर लेकर गए हैं SPICe+ में जिसमें video form आपको download करके internet के माध्यम से भर के फिर से upload करने की आवश्यकता नहीं है. अब आप एक के माध्यम से आप web based form available है आपके pass. सारे detail आप सु से सरलता से आप वहीं भर सकते हैं net पर ही. फिर उसके बाद आपको उसमें services जो है, additional services भी

मिल रही हैं अभी एक और form है जो Ag pro के नाम से है और जो भी आप करते हैं SPICe+ में वह सारी जो entries है वह memorandum में आ जाती है, articles में आ जाती हैं, जो भी attachment आप लगाएंगे उसमें जो सारे detail एक बारी ही यह आपने कहीं SPICe+ में भरे हैं. वह सारे दूसरी जगह पर जहां जहां उनकी ज़रूरत है वहां popular हो जाते हैं. तो यह digital technology का पूरा भरपूर उपयोग किया गया है SPICe+ form में. तो इसकी खासियत है कि अब जो हम हमले ने पहल करी थी तीन service इससे आज दस service तीन मंत्रालय और एक state government और कई अन्य rank इन सब की तरफ से जो services हैं एक form में एक बारी ही submit करने से यह आपको आप है. पानी जी बदलाव वाली जो बात हो रही थी तो बदलाव के बारे में कहा मोटी जी ने की बदलाव पर हमारी नज़र जाती है तो बदलाव बस से क्या? किस तरह के बदलाव होते हैं बदलाव करने क्या ज़रूरी क्यों जरा. सरकार stake holders की feedback लेती है और सरकार देखती है कि इसको और कैसे इसको सहूलियत और कैसे प्रदान की गए. उन feedback के basis पर यह कहा जाए कि अगर अभी तो हमने किया processing फिर हमें लगा कि क्या single window system जैसे भी कोई चीज़ हो सकती है जहां कि एक form के माध्यम से हम direct number दे दे, company inincorporation number तो दे रहे थे certificate of inincorporation. Name reserve करा दें. क्या हम दूसरी agencies चीज़ में फर्ज कीजिए कि किसी company को यह c और E upa phone number लेना हो. हमने कहा कि आप हमारे form जब आप corporate कर रहे हैं, हमारे form के माध्यम से आप ले लीजिए, आपको वह number मिल जाएगा. अभी नए बदलाव में हमने bank account की भी सहूलियत दे दी कि आप bank account ले ले इस form के माध्यम से. तो एक company जब शुरुआत करती है, company का गठन होता है. तो company को certificate of inincorporation थी company को एक bank account चाहिए. Company को और E p phone number चाहिए company को pant time चाहिए और हमने एक चीज़ कहा कि अगर आपको Gst number चाहिए तो वह भी सुबह विधायक optional तौर पर हम दे सकते हैं. बाकी numbers जो हैं वह हमारे mandatory हमने कहा कि आप नई company के लिए E को number यह इसी number और bank account तो आप हमें हमसे ही लेना है. इसी form के माध्यम से लेना है. जिससे कि आप आपकी असुविधा सुविधाएं खत्म हो जाए. उसके बाद महाराष्ट्र जो companies हैं. जी. वहां professional tax एक Pt number और Pti number लेना होता है. हमने कहा वह भी इसी form के माध्यम से ले. So यह बहुत बड़ी पहल है कि government of महाराष्ट्र, ministry of labor, department of re revenue और banks. इन इनसे सब लोगों ने एक meal के मिला ज प्रयास है यह. E for Number company के लिए अनिवार्य है number लेना. वह registration number हुआ. लेकिन अगर वह एक ratio है अगर उस को आप cross नहीं करेंगे suppose उनके उनके कानून में अगर एक है कि आपके pass इतनी employees का number होना चाहिए तभी आपको return भरने की ज़रूरत है हमारे. जी. वह हमने कहा कि जब आप cross करें तभी आप भरें लेकिन आप number ले लें. फिर आपको किसी और दफ्तर में जाकर number लेने की ज़रूरत नहीं है. अब एक single window system के माध्यम से आपको इतनी दस जैसा मूर्ति साहब ने कहा बाकी सुविधाएं भी मिल गई यह और यह वे form है. So web form की एक सबसे बड़ी सुविधा होती है. जी. कि पहले आप phone को download किया करते थे. अगर आपने पूरा काम नहीं किया so आपका

काम अधूरा रह गया. अब form में आप entry करें. Save होता रहेगा. आप उसको वापस जाकर जहां आपने receive किया फिर आप काम हम शुरू कर सकते हैं उसके बाद. और बहुत सारी fields जो है वह auto हो जाएंगी जैसा मूर्ति साहब ने कहा. जैसे एक declaration का form हमारा होता है वह auto popular हो जाएगा. उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. So काफी सरल बनाने की कोशिश की गई है. मतलब जो जानकारी SPICe+ पर आपने दी वह automatically दूसरी जो. Ring हैं linked हैं वह सारे सारे वही details fill जाएंगे अपने आप fail हो जाएंगे. अच्छा आपने इज pro की जो बात कही थी तो pro किस तरह उसमें और क्या जानकारी देनी पड़ता है. इज pro एक b of services के लिए बनाया गया है जिसके तहत आप Gst registration के लिए अच्छा. Registration के लिए provident fund के registration के लिए profession tax के session के लिए और bank account खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारा यह प्रयास है कि जब आप company शुरू करना चाहते हैं तो यह सारे जो register कि जिनकी आवश्यकता होती है एक आम company के लिए आपको पहले दिन से उपलब्ध. पहले दिन आपके लिए प्राप्त हों और एक ही बारी आपको form पर file करने की ज़रूरत पड़े. जी. एक चीज़ जो जो मेरे जहन में आ रही है चाहूँगा आशीष जी आप इस बात का जवाब लें. SPICe+ भी है जाहिर pro है, लेकिन क्या company का दायरा या company का स्तर किसी कोई छोटी company खोलना चाहता है, किसी की बड़ी company है. क्या सभी को इस तरह से इसी inincorporation के तरीके से गुज़रना पड़ता है? बिल्कुल देखिए पहले क्या होता था जब भी हम company बनाते थे जो आपने company बनाई उसका inincorporation certificate ले ली. अब वह incorporation लेने के बाद आप पहन के लिए apply करते थे pan आता था, bank के account के लिए apply करते थे. आप उसके बाद अलग अलग जो different registration sir ने बताएं इसी employees के लिए pro funds के लिए वह सब apply करने पड़ते थे. अब क्या होगा कि एक ही form के जरिए आप company इन inc incorporation के साथ में इतनी सारी value services पा. जहां तक आपने बात की company के दायरे की की कोई company छोटी या बड़ी है. यह कुछ ऐसे registration से जो लगभग इनमें से सारी कंपनियों के लिए applicable है. जिन companies पर वह requirement नहीं लग रही है वह सिर्फ number ले रख लिया अभी जिस दिन वह बड़े दायरे में आएगी वहां पर उन number को उपयोग करके वह अपना return 5 कर पाएगी. 5 plus अजय is pro through आपके pass एक साथ दस services available है. तो पहले दिन से आप छोटी company से लेकर बड़ी company के दायरे में पहले दिन से जो services आप उपयोग करना चाहें पहले दिन से आपके pass सारी उपलब्ध है. अगर आपने Gst number ले लिया तो तो फिर उसकी return भरनी पड़ेगी. नहीं भई आप उसके दायरे में है नहीं. वही जो sir ने बताया Gst number आपने ले लिया पर ministry of corporate of affairs ने दूसरे department के साथ यह up किया हुआ है कि यह number लेना हमने optional किया हुआ है. पर इसके return हमें तभी file करना पड़ेंगे जब हम fresh limit में आएँगे suppose आज वही साहब ने बोला जी. आज मैंने provident fund का number ले लिया. पर ऊपर applicable नहीं है तो वह number आपका राय क्योंकि हमने दूसरे department के साथ में tie किया हुआ है. आशीष जी ने जैसा कहा वह एक एक कहता ठीक है. जब तक Gst का सवाल है. जब मुझे बातचीत हो रही थी तो आशीष basically EPFO, ESIC number का ही का सवाल है. Actually जब मुझे बातचीत हो रही थी तो आशीष basically यह सारी number का ही

reference दे रहे थे. जहां तक Gst जो सवाल है. जी. वह optional है. So optional का मतलब यह हुआ कि आप हमारे यहां से ले सकते हैं या department of revenue से ले सकते हैं. हमसे लेना अनिवार्य में ही है. यह I For bank account number हम हमसे लेना अनिवार्य अगर आप team corporate कर आपसे अनिवार्य है लेकिन t पर जब पहुंचे तब आप return और Gst optional इसलिए है आप से लें या आप वहाँ से. मान लीजिए मैंने एक company अपनी शुरू की और मैंने Gst ले लिया और यह सोच ले लिया कि मेरा काम बार इतना होगा. लेकिन नहीं हुआ उतना. तो क्या मैं उसे अपने pass रखूं या surrender क्योंकि मुझे तो return file करना पड़ेगा. इस पर क्या राय देंगे आप? आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं जी अगर आपको लगता है futuristic कैसा होने वाला है कि आप t limit cross करने वाले हैं छह महीने में तो z रखिए otherwise आप nil की return भरते हुए बाद में finally उसको किसी भी वक्त अपना जो है वह surrender कर सकते हैं. अच्छा चर्चा में अब मैं एक बात लाना चाहता हूं क्योंकि ease of doing business कि जब हम बात कर रहे हैं तो t तिरसठ में पायदान पर भारत से समय जो कि क्योंकि हम हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है लेकिन एक बात जो audit को लेकर जो बात आती है और कंपनियों में जो जो कई बार जो हम सब पढ़ते हैं देखते हैं और हंगामे में जो होते हैं, उन पर जरा हम बात करें. Audit को लेकर क्या क्या है स्थिति आप आपसी शुरू करें. आशीष देखिए audit के विषय में अतुल जी financial audit के बारे में बात करें क्योंकि वह institute represent करते हैं. Non financial audit किए बात करूंगा. मैं उसके चौदह के बाद से secret audit mandatory हुआ है सारी company fresh का gap समझें. Secret audit company में जितने law लगते हैं, अलग अलग विभिन्न काट के जिसमें मुख्य company कानून है. तो company अधिनियम से related जितने भी कानून उनके ऊपर लगते हैं उसकी compliance का audit एक practicing company से secretary वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यह वह हो रहा है नहीं हो रहा है. उनका compliance हो रहा है या नहीं हो रहा. Company का information हुआ है. Company ने जो दूसरे rule है कानून हैं, वह सब तरीके से follow किए हैं कि नहीं. तो उसके लिए practicing secretary secret audit देता है. तो यह एक non financial audit है जो पहली बार दो हज़ार चौदह के बाद आया है. जब से लाभ होगा जरा यह बताइए. इससे जो सबसे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि compliance system जो है देश का वह सुधर क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो आप financial audit chartered accountants कर देते हैं बिलकुल तो हम financial चीज़ तो देख लेते हैं पर company मत यह चीज़ नहीं थी. Non financial हम नहीं देखते थे. तो उसके यह pre checking पहले से practicing company से criteria अपने certificate के माध्यम से करके दे देता है कि हां इन companies ने यह सारे कानून का proper follow किया हुआ है. तो वह काम बहुत easy हो जाता है मंत्रालय का भी क्योंकि जब एक third party certification या practicing company से secretary है secret audit certificate मिल जाता है तो उन्हें भी confidence रहता है कि हां ठीक है. अच्छा उसमें सबसे important है जो कानूनों का पालन नहीं किया है. उसके बारे में भू ज़िक्र करना है कि यह company ने particular rule का violation किया है. तो यह भी एक pr है ऐसी जानकारी. ज़िम्मेदारी किसकी? यह ज़िम्मेदारी practicing company से ज़िक्र है जो वह audit कर रहा है. उसको यह जानकारी company की audit report में लिख देना है कि company ने इस particular चीज़ को for नहीं लिख देते हैं लिखते थे. लिख लेते हैं. अतुल का reaction से पहले

आपसे और पांडे जी से दोनों से यह बात कि हां यह जानना चाहता हूं audit को लेकर जो चिंताएं रही हैं और जाहिर सी बात है फिर वह ease of doing business में अड़ अर्चना बनती हैं. आड़ आती है उसके. मंत्रालय का और आप लोगों का क्या नज़रिया है और इस दिशा में क्या आपने पहल किए या या क्या सोच है आपकी? मंत्रालय की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो view है वह यह जो statue और editors हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैं इनको कहूंगा कि pillar है corporate governance के companies act के तहत. जिसमें जिस बात की पुष्टि audit करता है. शायद ही कोई ऐसा कोई और इंसान होगा जो इस तरह की पुष्टि एक company के बारे में कर पाता है और करता है. तो हमारे लिए कानून के तहत भी एक दर्जा प्रदान किया गया है audit के लिए जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दर्जा है. Company कानून में कई सारे प्रावधान हैं जिसमें को कई सारी duties responsibilities और power दी गई है. कि वह किसी भी तरह का information जो है वह company से मांग सकता है, ले सकता है और उसके ऊपर अपने अपनी टिप्पणी और अपनी opinion उसको दे सकता है. हाल ही में हम लोगों ने एक नया company audit editors report order निकाला है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण order है जिसके तहत जो सारी बड़ी companyयां हैं कम से कम दो ढाई lakh जो भारत में जो सबसे बड़ी companyयां हैं. उन पर लागू है यह order जिसके audit के ऊपर इस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो आएगी ही आएगी लेकिन इसका इसका यह मतलब भी होगा कि उसके हाथ काफी मजबूती होंगे जिसके तहत वह company से और कहीं ज़्यादा information ले सकता है और companies को यह information देनी पड़ेगी. सरकार का यह मानना है कि जो statue audit है एक बहुत ही अहम् महत्वपूर्ण कड़ी और जिसको हमें सक्षम बनाना है महत्वपूर्ण बनाना है और इसके हमें और support देनी है और आगे बढ़ाना है. पानी जी यही सवाल मैं दूसरी तरह से पूछना चाहूँगा अब तक किस तरह की हैं? मंत्रालय ने देखी और और फिर उसके बाद जो जो इस तरह के कदम था. क्या सबसे ज़्यादा आपने दी? मैं एक आपको पहले पृष्ठभूमि दे दूं ज़रूर कि इनका इनका role कैसे है? Defined कैसे है हमारे हैं. तो एक तो chartered accountant जो कानून है वह हमारा 19 49 का act of Parliament से. फिर उसके बाद cost accountants का 19 59 का एक act है और company चीज़ का एक act है 19 80 का. So यह तीन जो हमारे cost accountants chartered accountants और company secretary हैं. यह तीन act of Parliament से govern होते. अच्छा. सुई इनका role भी statue भी role है. यह यहां से इनका गठन जब हुआ तो इनका फिर जो कहते हैं कि इनका जो इनकी भूमिका चली आती है corporate governance थे. तब companies law को यह कैसे govern करें? कैसे cost audit होनी चाहिए? कैसे financial audit होनी चाहिए और कैसे secretary audit होनी चाहिए. अगर यह तीनों भूमिका अगर यह भूमिका अच्छी तरीके से निभा जाए. तो corporate governance उत्कृष्ट वह होगा. तो यह ज़रूरी था कि इनके role को और strengthen किया गया. मूर्ति साहब ने कहा, तो corporate कार्य मंत्रालय ने उस पर काफी steps लिए इस जगह के audit में क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे करें. अभी एक paper भी निकाला गया है consultation paper जिसकी वजह से कहा गया है कि क्या audit details के role और क्या होनी चाहिए? वह consultation हो रहा है और यह कहा गया कि audit तो audit करती हैं. उनकी भी एक responsibility है. उनकी responsibility को और बढ़ाई गई कहा कि आपकी responsibility थी act के तहत. Particularly जो company act दो हज़ार तेरह जब आया आप उस उसके पहले

आपने देखा होगा कि कुछ companies जो हैं उनमें कुछ financial varieties पाई गई. अब उसको काफी उस act के बाद ऐसे प्रावधान ला दिए गए कि secretary audit करना है, punch audit और st हो गए. आपको cost account cost accountant का role defined किया गया. तो यह corporate governance को अच्छा बनाने के लिए यह तीनों का role काफी important है. तीनों institutes के role काफी भौतिक थे. The था कि हमारे को अभी मूर्ति साहब ने और pan साहब ने बताया कि हम सब लोग समय के साथ सीखते हैं. समय के साथ जो है वह नई नई चाहिए जो है वह हमारे सामने आती हैं, नए नए तरह के fraud सामने आते हैं नए तरह की challenge जी सामने आते हैं जिससे कि समय के साथ जो है वह अपने role को जो है वह g define किया जाता है. और जिस तरीके से पिछले दस बीस सालों के अंदर बहुत तरह के frauds हुए या बहुत तरह की regular पाई गई और उसकी वजह से कानून के अंदर भी बहुत सारे change गए जिम्मेवार को अलग तरीके से define किया गया. ज़्यादा chartered accountants को financial audit करते हुए ज़्यादा powers देने की बात की गई और उनका दायित्व भी बढ़ाया गया. मैं सिर्फ एक बात कहूंगा इसमें कि आप लोग जब हम लोग देखते हैं कि corporate governance की बात आती है तो दो बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझने की बात है कि एक होता है fraud और एक होता है regularly. तो जब हम fraud की बात **करते हैं और** regularly. तो जब हम fraud की बात करते हैं और अगर एक management ही अपने आप में कोई ऐसा काम करे जो एक minute के लिए किताबों के अंदर ही ना आ पाए तो उसके लिए तो आपको एक minute के लिए investigation का जो role होता है. हैं तो वह role जो है वह बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो चीज़ किताब अंदर ही नहीं आ पाई. तो लोग उदाहरण समझाएंगे तो दर्शकों को भी ज़्यादा बताया जैसे example की बात है कि कोई आपकी transaction करी वह किताबों के बाहर ही आपने transaction का ली है और वह पैसा आप उस तरीके से बाहर की बात आप जो है वह दूसरी तरफ ले गए. तो वह क्योंकि किताबों में नहीं आया तो colony के accounts में नहीं है. हां, company का accounts में नहीं आया तो audit जो है चाहे वह second trail और editor है data है financial audit है वह कुछ भी कर नहीं कर सकते. ठीक बात. तो उसके लिए अलग से क्योंकि हम लोगों ने जैसे forensic audit की बात हो रही है या उस तरह की बात होती है तो वह सब प्रावधान भी धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं. लेकिन जहां पर हम लोग जो हैं वह अपने regular की बात करें तो दो तीन चीज़ें हैं बड़ी important है जैसा कि सबने ने बताया कि कानूनों के अंदर change जैसे अभी नया का का हमारा एक नया provision आया उसी तरीके से consultation paper बात है उससे पहले भी क्योंकि हम लोग क्योंकि C झूठ जो हम chartered accountant institute की बात करते हैं वह एक regulator का role करता है. तो हमें भी ज़्यादा सरकार ने जो है वह power दिए कि आप जो है वह ज़्यादा सख्ती से अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई regular करता है तो आप ज़्यादा सख्ती से उनके साथ जो है कढ़ाई से उनके साथ जो है वह आप मैं कहूंगा कि उनको treat कीजिए. उनके साथ जो है behave करिए ताकि जो है वह कहीं ना कहीं पर death trend के रूप में हर एक व्यक्ति जो है वह अपने आप में अपने role को जो है वो और ज़्यादा मजबूती से जो है वह उस चीज़ को देखें. जी. तो एक तीसरी चीज़ जो important थी वह थी skills की तो हम लोगों ने even पीछे जो है वह के अंदर अपना दो हज़ार सत्रह में एक नया syllabus आदमी है प्रधानमंत्री साहब ने launch किया वह एक नया syllabus भी हम लोगों ने launch किया जिसके अंदर हमने national bench marking को

achieve करते हुए यह कोशिश करी हमारे members को ज़्यादा से ज़्यादा नई skills जो है forensic की skills हैं या दूसरी skills हैं वह अपनी जाए ताकि जो है वह corporate governance के अंदर जो है वह मजबूती तरीके से अपने जो है वह country boot कर सके. लेकिन corporate governance में कोई और भी रहती है जिसके ऊपर मैं देख पाता हूं कि कई और initiative भी लिए गए हैं तो खाली audit का role नहीं जैसे audit committee का role है जो company के अंदर audit committee होती उसका role क्या रही कैसे रही? तो उनके ऊपर भी लगातार जो है वह हम और सरकार मिलकर चर्चा करते रहते हैं और उसमें भी कई कहीं पर नई changes या नई improvement लाने का प्रयास जारी जाता है. जी यह मैं इस बात को थोड़ा सा और दूसरी तरह से भी समझना चाहता हूं और वह यह कि आपने body find किया frauds एक तरफ और a regulatory दूसरी तरफ. अमूमन, alter से किस तरह की गलतियां ज़्यादा हो जाती है. क्या experience है आपका? क्या क्या आपको लगता है कहां चूक होती है? जो बार बार एक तरह की कुछ चूक होती थी या होती है या जिसके लिए हम लोग धीरे धीरे करके जैसे मैंने बोला कि skill set change हो रहे हैं या requirement change हो रही है वह होता है कि जैसे expose कीजिए एक sam. क्योंकि audit जो है वह जब अगर मान लीजिए किसी company के अंदर दो lakh पांच lakh transactions है तो वह हर transactions को within पंद्रह दिन एक महीना लगा के उसको check नहीं कर सकता तो वह करता है और sam करने के अंदर अगर वह sample करते वक्त उससे गलती हो गई. Ultimately क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो है वह आपका एक बड़ा segment हो सकता है कि वह छूट जाए जिसको उसे जो है वह audit करना चाहिए. तो उस बात को ध्यान में जैसे मान लीजिए हम लोगों ने आगे चलके के members को forensic की training दे रहे हैं ताकि sam के ऊपर जो है वह जितना कम से कम आप वह करें मतलब sample से hut जाए और आप ना technology use करके सारे transactions को check करें. वह अपने आप में एक एक बड़ा जो है वह विषय था जहां पर member जो है वह generally मैं कहूंगा कि चाहते हुए भी जो है वह उन चीज़ों को पूरा check नहीं कर पाते थे जितना cheque उनको एक minute के लिए शायद अपने आप में जो है वह क्योंकि आज एक कहावत होती है कि there is everything for the need but not not for the greed. तो अगर एक minute के लिए जब हम जब हम economic system में बात करते हैं commercial system में बात करते हैं तो आपको जो है और ज़्यादा सजग रहना पड़ता है. Sc हम जिस हम word use करते हैं. तो sk जो है वो और ज़्यादा मजबूती से आपको implement करना पड़ता है. तो वहां पर इस तरह की चीज़ें थी जहां पर हमें लगता था जो दूसरी चीज़ें है जैसे example की बात है कि हमारे pass international benchmarks हैं standards जिसे हम inter accounting standards बोलते हैं या audit standards बोलते हैं. तो क्योंकि वह लोग st जो हैं वह बड़े sting होते हैं बड़े तरीके से उनको वह करना होता है. तो हम लोगों का यह होता था कि कई बार ऐसा होता था कि किसी standard का कहीं पर follow नहीं किया गया है. तो जब audit हुआ था उसमें उन्होंने उस बात को report नहीं किया कि आपने standard follow नहीं किया है. तो उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा training हो सकती है या जितना ज़्यादा ज़्यादा को easy किया जा सकता है. उनके ऊपर भी लगातार जो है वह झूठ काम करता रहता है. पांडे जी मैं चाहता हूं आप और मूर्ति जी इस सवाल के जवाब हैं. कि के role में अगर कहीं कोई चूक हो जाती है तो क्या system में ऐसा कुछ है कि कोई step follow नहीं हो पाया, अनदेखा रहे गया. इसको

इसको plug करने के लिए क्या क्या हमारे pass तरीका होगा. अब जैसे भारत ने यह ठान है कि एक पांच trillion economy बननी है हमको अगले कुछ कुछ सालों में. इसका मूल उधार जो है वह मूल वह नीति और नैतिकता से काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. उसमें audit को सक्षम करने के लिए जो जैसे हमारे को गुप्ता साहब ने बताया कि जो standard होते हैं audit standard. इनका इनके हिसाब से चलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है. जो Indian audit standards हैं वह मूल रूप है जो global audit standards हैं उनके ही level के हैं उसमें कोई खामी नहीं है. इसकी ज़रूरत है कि company जो है proper information दें audit को और audit जो है standards के हिसाब से अगर अपना audit conduct करेगा. तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई गुंजाइश रह जाएगी कि information रह जाएगी या ऐसी कोई गुंजाइश रह जाएगी कि audit editor जो है जिन पहलुओं पर उसको खास नज़र या तब वह j डालने की ज़रूरत है वह नहीं डाल पाएगा. अब बात आती है invest education की और और उनके protection fund की. तो उस authority के आप Ceo है. यह यह क्या विचार है? इस का पूरा जरा हमें समझाएं और यह किस तरह से काम कर रहा है. See investor education protection front authority का ग time company अधिनियम दो हज़ार तेरह के तहत हुए है. तो एक section है 1 25 of company act. उसके तहत यह authority का गठन हुआ. उसके पहले दो हज़ार तेरह के पहले education fund हुआ करता था. Company के company कानून के तहत अगर सात साल तक आपने dividend नहीं clean किए जी. So वह dividend investor education को एक fund में चला आता था. उसके साथ दो हज़ार तेरह में फिर कहा गया कि अगर हमारे pass dividend हैं. So हम इसके holders जो हमारे हैं जिनके वह थे जो right lemon को कहा जाए उनको हम लौटा सकते है. So दो हज़ार तेरह के तहत एक progressive relief relation लाया गया है section 1 25 के तहत और कहा गया. कि हम जो cl हैं जिनके dividend हमारे pass आ गए, अब dividend कैसे आते? जैसे आपके address change हो गए. आपका bank account change हो गया. आप एक शायद से दूसरे शहर चले गए. आपके pass dividend आए और return back हो गए companies के pass. Jump ने अपने भी discount में रख लिया. जी. उसके बाद सात साल हो गए उन्होंने education protection fund में transfer या माता पिता के नाम में थे वो नहीं रहे वह भी उनके शहर उनके नाम पर बोल नहीं रहे वह चले यार. दो हज़ार तेरह के पहले वह investor education fund में आते थे और उसका होता था केवल education और awareness के लिए. दो हज़ार तेरह के बाद कहा गया कि अब हम अगर कोई करता है. पहले तो claim करने का प्रावधान किया गया और claim होने के बाद हम उसे लौट आऐंगे. उसके बाद dividend के साथ जो underline shares है. जी. वह shares भी सात साल के बाद अगर आपने सात साल लगातार dividend नई claim किए. So जो underline shares है वह भी regulation protection fund authority के pass चले आते हैं. सुरक्षित रहते हैं. सुरक्षित है. अच्छा और काफी बड़ी तादाद में है. उनसे for dividend. तो दो हज़ार तेरह सोलह में दो हज़ार तेरह कानून के तहत लाया गया और दो हज़ार सोलह सितंबर के में यह authority का गठन हुआ. अब वह कोई भी cl एक online form file कर सकता है. जिसको 5 कहते हैं, जिसके तहत वह share और dividend claim कर सकता है. Authority से. अच्छा. Authority उसकी उन उस clean को देखकर verify करेगी और कम इतनी उसको verify करके company से कहेगी कि आप देख कि यही आपके record में कभी थे

यह cl company कहेगी आएगी हां यह हमारे थे हमारे record में. Register पर थे, इनके shares हैं, इनके dividend हैं जब उन्होंने verify कर दिया. वह पंद्रह बीस साल पुराने अभी के भी हो. जी हां और अच्छा. जी हां, कितने भी पुराने हो, सात साल के बाद तो आती ही है Ip authority में. अच्छा. सात साल के पहले तो होंगी ही लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने कहा और company ने कह दिया हां यह सब online प्रक्रिया. यह भी online है. तो हम उनके bank के account में online transfer करते हैं और share उनके demat पर transfer करते उनको demat account अगर नहीं है तो खोलना पड़ेगा. खोल demat account आपको खोलना पड़ेगा. अच्छा. क्योंकि आजकल तो सारे demat account है. So आपके वह demat account में भी transfer हो खाएंगे. वह एक बहुत बड़ी पहले सरकार की जिसको ease of doing business से थोड़ा हटके के हम ease of living के लिए भी कह सकते हैं. कि अब आप आपके कोई पैसे हैं, कोई शहर है जिसको आपको आप shares और खोया. वह आपको वापस मिल रहे. डूबा डूबा हुआ था डूबा हुआ धन वापस वापस. So यह बहुत बड़ी सुविधा सरकार नीति दी है. बात और बताइए भा जी. छोटे investors की जब बात आती है और खासतौर तौर पर अगर हम बात करे भारत इतना बड़ा देश है. यह क्या हमारा focus ज़्यादा शहरों पर या गांव में भी जो छोटा investor है उसको लेकर भी उसके protection की भी बात है. मैं बताना चाहूँगा कि this education protect fund authority जो का काम केवल claim settlement ही नहीं है. एक बहुत बड़ा जो role है, दायित्व तो है वह investor को aware करना और educate करना. Attack करना भी protect करना किससे? Product इनकी scheme से po scheme से जो छोटी छोटी जगहों गौ पर चलती है. Fly by night operators हैं वह चले जाते. वह पैसे लेकर और suddenly वह विलुप्त हो जाते हैं मिलते नहीं है. जी. उसके उसके लिए education protest fund authority नहीं. Ca का governance है, उसका आपने नाम सुना होगा Ca governance. के साथ mou किया. नेहरू युवा के secretary के साथ Mou किया और bank of baroda दा kotak mahindra bank के साथ हमारे mou हुए. हमारा Mou जो है वह department of post के साथ हुआ. India post payment bank के साथ हुआ. यह सारे जो है ग्रामीण में भी काम कर रही हैं. India post payment bank तो गांव गांव तक है. हमारे को वह फ़ैला रहे हैं. ले जा रही है. लोगों तक और C governance का तो role हर छोटे छोटे कस्बों में भी Cs governance है. वहां के volunteers जाते हैं उनको investor को educate करते हैं, aware करते हैं और हमारा एक portal है Ips portal जिसमें कि success stories हैं लोगों की लोग बता रहे हैं कि इस education के माध्यम से हमने bank account खुलवा दिया. हमें हमें पता लगा कि अच्छा पैसे ही cash में रखना रख से अच्छा तो हमें invest करना चाहिए. Investment के instruments क्या हो सकते हैं? अच्छे instrument क्या है? यह हमने किया. So कई हम एक memorandum of understanding के माध्यम से दूध छोटे मोटे शहर, गांव सब में एक मुहिम शुरू की. उसके बाद हमने state living conference से शुरू किया. So पहला state level conference हमने भुवनेश्वर में किया. वहां हमने पंचायत से लोगों को बुलाया. पंचायत की महिलाएं पंचायत के लोग नेहरू वाकई हिंसक attend के युवक जो volunteers है वह यह सभी लोग आए पूरे उड़ीसा से बड़ी तादाद लोग आए. तो वहां हम ने उन लोगों को train किया कि कैसे करना है कैसे सुरक्षित निवेश कैसे करना है और आप प scheme से बचे product scheme से बचें क्योंकि आप अब आपकी अपने धन का सवाल है. अब हम हर state में conference जन जाग अभियान के से हम हर

state जाएंगे. चलते चलते मैं यह चाहूँगा कि मूर्ति साहब आपसे शुरू करके और आप सब की टिप्पणी चाहूँगा कि अब corporate governance के माहौल में और ease of doing business की जो नई पायदान जो भारत चढ़ जा रहा है, हम आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन क्या बदलाव देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि भारत trillion economy की तरह निरंतर अग्रसर करेगा और जो नैतिकता और नीति से काम करने की जो मूल भावना है यह हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि यह एक और ज़ोर पकड़ेगा और बड़ी शक्ति से ज़ोर पकड़ेगा यह और इसमें अहम् भूमिका होंगी जो भारत के में जो companies हैं और जो हमारे professional साथी हैं chartered accountant ins से company से institutes है cost accountant institutes से और legal professional के जो लोग हैं इनमें एक मूल भावना और करे और कई शक्तिशाली भावना जागे कि हम लोगों को निरंतर अग्रसर इस मुकाम पर पहुंचना है. आशीष. हम एक सौ सैंतालीस से 3 तिरेसठ paper आए हैं. पचास के अंदर तो आ जाए है पर हम कोशिश करेंगे top 10 में आने की क्योंकि आज हम जब 5000000000000 economy बनते हैं तो विश्व की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थानों में से एक आज भी हैं यदि हम वहां पर पांचवे number पर आऐंगे. तो हम ease और doing में दस number के अंदर आऐंगे यही मेरा और शायद सबका थे. पानी जी जी. मुझे लगता है कि जिस ढंग से policy बन रही है निर्धारण हो रहे हैं और जैसे युवा भारत है यह अब नई सोच है और एक प्रगति की तरफ सभी लोग लगे हैं. सभी लोगों का प्रयास है कि भारत सशक्त हो. कैसे आगे बढ़े? कैसे तेजी से आगे बढ़े यह सोच है और जो हमारी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री कि जो सोच है और जो वह चाहते हैं कि दो हज़ार चौबीस तक हमें पांच million dollar economy पर पहुंचना है. अगर यह सारे तत्व मिल जाएं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम ज़रूर ही उसको हासिल करेंगे और उसे आगे बढ़ जाएंगे. जी. बिल्कुल sir जैसा कि मनोज पांडे जी ने कहा कि अगर जिस तरीके से हम लोग पीछे बीस वर्ष से और आज का दृश्य देखते हैं. तो जो ease of doing का माहौल है जो मैं कहूँ हर चीज़ आपके pass आज को available है technology का जिस तरीके से हम लोगों ने use करना शुरू किया है. Iit के अंदर हम एक महा शक्ति है और फिर जिस तरीके से हमारे जो यह युवा हैं वो startups की बात करते हैं या दूसरी technology को use करने की बात करते हैं और उसके बाद एक जो environment corporate cover का धीरे धीरे करके जो है वह एक सशक्त बनता जा रहा है. तो हम लोग जो है वह पांच लेने economy के साथ साथ economy की बात भी जो है शायद दो हज़ार तीस तक जो है वह हम अपने अच्छे से कर सकते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब जो हैं वह जो co way में जिस तरीके से co way में की जा रही हैं और सभी लोग अपना अपना जो role है वह बखूबी निभा रहे हैं तो उससे जो है वह हिंदुस्तान जो है हमारा जो भारत देश है वह अब आप में एक महा शक्ति के रूप में economic शक्ति के रूप में और even एक बात मैं और touch करना चाहूँगा कि sustainability के साथ तो जो है वह बड़ी important है तो वह भी अपने आप में जो है achieve होने जा रही है. K मूर्ति साहब आशीष जी, मनोज पांडे जी अति गुप्ता जी और यहां I chartered accountants आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप इस चर्चा में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात यही कि व्यापार एक बार करने की बात नहीं है. कि आपने किया? मुनाफा कमाया और बाहर निकल गए. बार बार जो चर्चा में बात I नीति नैतिकता की इसके साथ निष्ठा भी जोड़ और फिर देखिए देश कहां से कहां पहुंचता है? बड़ी बातें करना एक तरफ बड़ी बातों पर अमल करना. अब वक्त है और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि हम पहले से कितना

बेहतर हुए हैं. बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाज़िर होंगे नहीं मेहमानों के साथ तब तक के लिए नमस्कार.